न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया के समक्ष

इंद्रजीत बहल और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाता

सिविल रिट याचिका सं. 9120/1990

10 सितम्बर, 1990

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 19 (1) और (ग), 19 (4), 19 (6), 300-ए - विश्व मामलों की भारतीय परिषद अध्यादेश, 1990 - अध्याय 2, 4 से 11, 15, 23 - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 - मौलिक अधिकार - विश्व मामलों की भारतीय परिषद अध्यादेश - एक सोसाइटी को निकाय कॉर्पोरेट में शामिल करना - सोसाइटी की संपत्ति को निकाय कॉर्पोरेट में शामिल करना - सोसाइटी की सदस्यता और पद धारण करने का अधिकार असंवैधानिक करार दिया।

अभिनिर्धारित किया कि, अध्यादेश के प्रावधानों ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाया है क्योंकि याचिकाकर्ता जो विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पदाधिकारी हैं, चर्चा की व्यवस्था करके संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित अपने अधिकार का उपयोग करने के हकदार हैं। व्याख्यान, विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान। अध्यादेश के तहत पदाधिकारी का कार्यकाल और मौजूदा सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अध्यादेश के प्रावधानों ने याचिकाकर्ताओं को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया है।

(अनुच्छेद 10)

अभिनिर्धारित किया कि, इसके अलावा सोसायटी की परिसंपत्तियों को मनमाने ढंग से नई परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया है। किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना सोसायटी के सदस्यों को

संपत्ति से वंचित करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। जहां तक समाज की परिसंपत्तियों को बिना मुआवजे के अध्यादेश के तहत गठित कॉरपोरेट निकाय को हस्तांतरित करने से संबंधित प्रावधानों का संबंध है, वे मनमाने, अनुचित और मनमौजी हैं। यह प्रावधान भी भेदभावपूर्ण है। यह भेदभाव किसी तर्कसंगत आधार पर आधारित नहीं है। इसलिए, अध्यादेश के प्रावधान स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

(अनुच्छेद 16)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि इस माननीय न्यायालय से बहुत ही अनुरोध किया जाए: -

1. 30 जून, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय विश्व कार्य परिषद अध्यादेश, 1990 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (ए) से (सी) के अति वायरस घोषित किया गया है और इसलिए असंवैधानिक और शून्य घोषित किया गया है;
2. प्रतिवादियों और उसके अधिकारियों को उक्त अध्यादेश के प्रावधानों को लागू न करने और प्रभावी बनाने से रोकने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट या रिट जारी करना;
3. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी 30 जून, 1990 के नोटिस को रद्द करते हुए सर्टिओरारी की रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 को विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पहले निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था;
4. अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दें और प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता को समाप्त करें;
5. याचिकाकर्ताओं को इस रिट याचिका की लागत प्रदान करें।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अनुलग्नक पी -1 और पी -3 के संचालन पर रोक लगाई जाए।

सी. धुरीवाला, एडवोकेट, निधि गुप्ता, एडवोकेट के साथ, हरभगवान सिंह और के. के. कुकारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

जी. एस. बरार, वरिष्ठ स्थायी वकील मंजीत सिंह, एडवोकेट के साथ, उत्तरदाताओं के लिए.

निर्णय

न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया-

1. याचिकाकर्ताओं ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी विश्व मामलों की भारतीय परिषद अध्यादेश, 1990 के प्रावधानों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि लागू अध्यादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (1) (ए) और 19 (1) (सी) का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता नंबर 1 इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, चंडीगढ़ शाखा के अध्यक्ष हैं और याचिकाकर्ता नंबर 2 इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे भारतीय नागरिक हैं और लागू अध्यादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और 19 (1) (सी) के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

विश्व मामलों की भारतीय परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। सोसायटी वर्ष 1943 में पंजीकृत की गई थी। प्रारंभिक सदस्य सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे: जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, सर आर्देशिर आर दयाल, सर मौरिका ग्वायर, डॉ एम आर जयकर, श्री हिरदय नाथ कुंजरू, सर श्री राम, श्रीमती विजय ए लक्ष्मी पंडित, श्री एस शिवा राव, डॉ के एन काटजू, श्री टी टी कृष्णमाचारी, श्री एम आर मसनानी, श्री देव दास गांधी और अन्य। सोसाइटी का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अध्ययन और अनुसंधान के लिए स्वतंत्र केंद्र स्थापित करना था। सोसायटी का गठन गैर-आधिकारिक, गैर-राजनीतिक और गैर-लाभकारी कमाने वाले संगठन के रूप में किया गया था। उपनियमों में निर्धारित उद्देश्यों में से एक निम्नानुसार है -

> "भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के अध्ययन को बढ़ावा देना ताकि इसी तरह की गतिविधियों में लगे भारत और विदेशों के अन्य निकायों के साथ अध्ययन, अनुसंधान, चर्चा,

व्याख्याताओं, विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान आदि के माध्यम से विश्व मामलों और भारत के संबंधों के बारे में सूचित राय का एक निकाय विकसित किया जा सके।

3. भारतीय विश्व कार्य परिषद अध्यादेश, 1990 (संक्षेप में, अध्यादेश) नामक अध्यादेश के माध्यम से, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है और इसे एक निगमित निकाय में शामिल किया गया है। अध्यादेश की धारा 2 विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करती है। अध्यादेश की धारा 4 ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद का गठन भारतीय विश्व मामलों की परिषद के नाम से एक कॉर्पोरेट निकाय में किया है। इस निकाय के पास इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्हरण, स्वामित्व और निपटान करने की शक्ति के साथ एक समान मुहर होगी और उस पर मुकदमा किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अध्यादेश की धारा 4 के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत मौजूदा परिषद यानी विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को अध्यादेश की धारा 4 के तहत शामिल विश्व मामलों की भारतीय परिषद में निहित किया गया है।

4. अध्यादेश की धारा 5 के प्रावधान इस प्रकार हैं:-

5(1) नियत दिन पर और उसके बाद–

i. उस दिन से ठीक पहले मौजूदा परिषद में निहित सभी संपत्तियां और अन्य संपत्तियां परिषद में निहित होंगी;

ii. मौजूदा परिषद के उद्देश्य के लिए या उसके संबंध में उस दिन से ठीक पहले या उसके ठीक पहले मौजूदा परिषद के साथ या उसके लिए किए जाने वाले सभी ऋण, दायित्व और देयताएं, किए गए सभी ऋण, दायित्व और देयताएं, किए गए सभी मामलों और चीजों को परिषद के साथ या उसके लिए किया गया माना जाएगा;

iii. उस दिन से ठीक पहले मौजूदा परिषद को देय सभी धनराशि को परिषद को देय माना

जाएगा;

iv. उस दिन से ठीक पहले मौजूदा परिषद द्वारा या उसके खिलाफ स्थापित किए गए सभी मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाहियां, परिषद द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकती हैं या स्थापित की जा सकती हैं; और

v. उस दिन से ठीक पहले मौजूदा परिषद के अधीन कोई पद धारण करने वाला प्रत्येक कर्मचारी उस दिन परिषद के अधीन अपने पद या सेवा को पेंशन, उपदान और अन्य मामलों के समान अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो उसे स्वीकार्य होते यदि ऐसा कोई निहित नहीं होता; और ऐसा तब तक करना जारी रखेगा जब तक कि परिषद के तहत उसका रोजगार विधिवत समाप्त नहीं हो जाता है या जब तक परिषद द्वारा उसके पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों को विधिवत रूप से बदल नहीं दिया जाता है।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या इस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस धारा के तहत परिषद द्वारा अपनी नियमित सेवा में किसी भी कर्मचारी का समामेलन ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा और किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण।

5. अध्यादेश की धारा 6 में परिषद की संरचना दी गई है जो इस प्रकार है:-

(6) (1) परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

i. केंद्र सरकार के विदेश मंत्री, जो पदेन राष्ट्रपति होंगे;

ii. निदेशक, पदेन;

iii. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले चार सदस्य जो कूटनीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं;

iv. राजनयिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, वैश्विक अर्थशास्त्र, रणनीतिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले नौ सदस्य;

v. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले चार सदस्य जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित हैं;

vi. विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य;

vii. प्रख्यात मीडियाकर्मियों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य;

viii. संसद के चार सदस्य, जिनमें से लोक सभा और राज्य सभा से दो-दो सदस्य क्रमशः लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किए जाएंगे;

ix. केन् द्र सरकार द्वारा चार सदस् यों को पदेन रूप से शिक्षा, विदेश, वित् त और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित केन् द्र सरकार के मंत्रियों का प्रतिनिधित् व करने के लिए नामित किया जाएगा।

2. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि परिषद के सदस्य का पद संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं करेगा।

3. एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह:-

   i. एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार की राय में, नैतिक अधमता शामिल है; नहीं तो

   ii. एक निर्वहन दिवालिया है; नहीं तो

   iii. वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है।

6. अध्यादेश की धारा 7 में प्रावधान है कि पदाधिकारियों और सदस्य का कार्यकाल नामांकन की तारीख से तीन साल का होगा। अध्यादेश की धारा 7(5) केंद्र सरकार को किसी भी सदस्य को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद परिषद से हटाने की शक्तियां प्रदान करती है। अध्यादेश की धारा 8 राष्ट्रपति की शक्तियां प्रदान करती है। धारा 9 उपराष्ट्रपति की शक्तियां प्रदान करती है। अध्यादेश की धारा 10 परिषद के सदस्यों को भत्तों के भुगतान से संबंधित है। बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया अध्यादेश की धारा 11 में निर्धारित की गई है। अध्यादेश की धारा 15 में परिषद के कार्यों को निर्धारित किया गया है। अध्यादेश की धारा 23 परिषद की नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है।

7. भारत संघ की ओर से एम. वी. तुली, उप सचिव, (समन्वय), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लिखित बयान दायर किया गया है। भारत संघ का रुख यह है कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। अध्यादेश के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (एल) (ए) और 19 (1) (सी) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

8. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का मुख्य उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के अध्ययन को बढ़ावा देना था ताकि अध्ययन, अनुसंधान, चर्चा, व्याख्यान, विचारों और सूचना के आदान-प्रदान आदि के माध्यम से विश्व मामलों और उससे भारत के संबंधों के बारे में सूचित राय का एक निकाय विकसित किया जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सोसायटी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक करना, अनुसंधान, चर्चा, व्याख्यान, विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना था। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सभी नागरिकों को प्रदत्त भाषण और चर्चा की स्वतंत्रता के कारण संभव हुआ। अध्यादेश जारी होने के साथ ही मौजूदा सोसायटी के पदाधिकारियों का पद समाप्त हो गया है। अब सदस्यों और पदाधिकारियों को सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से नामित किया जाता है। परिषद के कार्यकरण में मौजूदा सदस्यों की कोई भूमिका नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने और

संविधान के अनुच्छेद 19: (1) (सी) के तहत अपनी पसंद का संघ बनाने के याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार को अध्यादेश की घोषणा से पूरी तरह से छीन लिया गया है। सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्य विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के उद्देश्य से चर्चा, व्याख्यान के रूप में महत्वपूर्ण सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। अध्यादेश जारी करके, अंतरराष्ट्रीय मामलों की समस्याओं पर राय व्यक्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया है।

9. बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने[1] कंपनी के शेयर धारकों के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार पर विचार करते हुए कहा कि -

"एक शेयरधारक अनुच्छेद 19 के संरक्षण का हकदार है। यह व्यक्तिगत अधिकार इस तथ्य के कारण नहीं खोया जाता है कि वह कंपनी का शेयरधारक है बैंक राष्ट्रीयकरण मामले (सुप्रा) ने इस दृष्टिकोण को स्थापित किया है कि नागरिकों के रूप में शेयरधारकों के मौलिक अधिकार तब नहीं खोए जाते हैं जब वे एक कंपनी बनाने के लिए संबद्ध होते हैं। जब शेयरधारकों के रूप में उनके मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई से बिगड़ा होता है, तो शेयरधारकों के रूप में उनके अधिकार संरक्षित होते हैं। कारण यह है कि यदि कंपनी के अधिकार प्रभावित होते हैं तो शेयरधारकों के अधिकार समान रूप से और आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। अनुच्छेद 19 (एल) (ए) के संबंध में शेयरधारकों के अधिकारों को निगम के माध्यम से शेयरधारकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले समाचार पत्रों द्वारा पेश और प्रकट किया जाता है। वर्तमान मामले में, संपादकों, निदेशकों और शेयरधारकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकारों का उपयोग उनके समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है जिसके माध्यम से वे बोलते हैं। प्रेस अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुंचता है। शेयरधारक अपने संपादकों के माध्यम से बोलते हैं। तथ्य यह है कि कंपनियां याचिकाकर्ता हैं, इस अदालत को शेयरधारकों, संपादकों, प्रिंटरों को राहत देने से

[1] ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 106.

नहीं रोकता है, जिन्होंने कानून के प्रभाव और उनके अधिकारों पर कार्रवाई के कारण अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, जो विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पदाधिकारी हैं, चर्चा, व्याख्यान, विचारों और सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था करके संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित अपने अधिकार का उपयोग करने के हकदार हैं। अध्यादेश के तहत पदाधिकारी का कार्यकाल और मौजूदा सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। सोसायटी की परिसंपत्तियों को मनमाने ढंग से नई परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया है। अध्यादेश के प्रावधानों ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया है। इस मौलिक अधिकार को केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (6) में उल्लिखित आधारों पर विनियमित किया जा सकता है। भारत संघ के वकील संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के किसी भी प्रावधान पर मेरा ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध को उचित ठहराया जा सकता है। मेरी राय है कि अध्यादेश के प्रावधानों ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाया है।

11. याचिकाकर्ता इस आधार पर भी समान रूप से मजबूत हैं कि अध्यादेश के प्रावधान संघ बनाने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 19 (1) (सी) अप्रतिबंधित शब्दों में सभी नागरिकों को संघ और संघ बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बेशक, याचिकाकर्ताओं ने इंडियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स नामक एक पंजीकृत सोसायटी का गठन किया। यह एक संघ था जो उस उद्देश्य के साथ सहयोग ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्य के साथ बनाया गया था, एसोसिएशन के पदाधिकारी विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के उद्देश्य से चर्चा, व्याख्यान की व्यवस्था कर रहे हैं। इस संघ ने विश्व मामलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। अध्यादेश के तहत याचिकाकर्ताओं से सोसायटी की सदस्यता का अधिकार छीन लिया गया है। इसके अलावा, सोसायटी की सभी संपत्तियों को किसी भी मुआवजे

के भुगतान के बिना परिषद को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को संघ बनाने के लिए अनुच्छेद 19 (1) (सी) द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। अनुच्छेद 19 (1) (सी) के अनुसार संघ बनाने के मौलिक अधिकार को केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (4) में निर्धारित सीमा तक विनियमित किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 19 (4) इस प्रकार है: -

"19 (4) उक्त खंड के उप-खंड (सी) में कुछ भी किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक कि उसने भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, उक्त उप-खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून बनाने से राज्य को रोका या रोका है।

12. भारत संघ के वकील यह बताने में सक्षम नहीं हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 (4) के किस प्रावधान के तहत अध्यादेश के प्रावधानों को उचित ठहराया जा सकता है। बेशक, अध्यादेश भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित नहीं है और न ही यह सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। एसोसिएशन बनाने के अधिकार को केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (4) में निर्धारित के रूप में विनियमित किया जा सकता है। अध्यादेश का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (4) में उल्लिखित किसी अन्य आधार के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा, अध्यादेश के प्रावधान मनमाने हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं के एसोसिएशन के पदाधिकारी होने के अधिकार के साथ-साथ सदस्यता भी मनमाने ढंग से छीन ली गई है। सोसायटी की परिसंपत्तियों को भी परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया है। ऊपरी तौर पर, अध्यादेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध याचिकाकर्ताओं को पदाधिकारियों के रूप में बने रहने के अधिकार और एसोसिएशन की सदस्यता से वंचित करते हैं। आगे एसोसिएशन को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती दमयंती नारंगा बनाम भारत संघ[2] मामले में इसी प्रकार के अधिनियम के उपबंधों पर विचार किया है। संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति भगवती ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

[2] **ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 966.**

"एसोसिएशन बनाने के अधिकार का अर्थ है कि एसोसिएशन बनाने वाले व्यक्तियों को केवल उन लोगों के साथ जुड़े रहने का अधिकार है जिन्हें वे स्वेच्छा से एसोसिएशन में स्वीकार करते हैं। कोई भी कानून, जिसके द्वारा सदस्यों को स्वैच्छिक संघ में पेश किया जाता है, सदस्यों को बाहर रखने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता है, या कोई भी कानून जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होने वालों की सदस्यता छीन लेता है, एक संघ बनाने के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम केवल मूल समाज के मामलों के प्रशासन को विनियमित नहीं करता है, यह समाज की संरचना को बदलने के लिए करता है। संरचना में इस परिवर्तन का परिणाम यह है कि जिन सदस्यों ने स्वेच्छा से एसोसिएशन का गठन किया था, वे अब उस एसोसिएशन में अन्य सदस्यों के साथ कार्य करने के लिए मजबूर हैं, जिन्हें अधिनियम द्वारा सदस्यों के रूप में लगाया गया है और जिनकी सदस्यता में प्रवेश में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। एसोसिएशन की संरचना में इस तरह का परिवर्तन स्पष्ट रूप से एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में कार्य करना जारी रखने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है जो मूल संस्थापकों द्वारा स्वेच्छा से गठित किया गया था। इसलिए, अधिनियम अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत गारंटीकृत संघ बनाने के लिए सोसाइटी के मूल सदस्यों के अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 19 (4) इस तथ्य पर कि इसे अधिनियम की वैधता का दावा करने के लिए सहायता में नहीं कहा जा सकता है। अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से सोसाइटी के संविधान में परिवर्तन भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में नहीं है। एक बार धारा 4 को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो पूरा अधिनियम अप्रभावी हो जाता है क्योंकि नए सम्मेलन का गठन अधिनियम में निहित अन्य सभी प्रावधानों का आधार है।

13. उपर्युक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह आवश्यक रूप से एसोसिएशन के साथ जुड़े रहने के अधिकार को दर्शाता है। संविधान द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि समाज के संविधान में भारी परिवर्तन किया जाता है ताकि सदस्यों को समाज के सदस्य के रूप में कार्य करने के अधिकारों को छीन लिया जाए, तो यह

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, 1962 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) का उल्लंघन करते हैं। वर्तमान अध्यादेश के प्रावधान प्रकृति में अधिक कठोर हैं। मेरी राय है कि यह मामला उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। उपरोक्त विनिर्णय के अनुपात को उच्चतम न्यायालय द्वारा असम राष्ट्र-भास प्रचार समिति और अन्य बनाम असम राज्य मामले में अनुमोदित किया गया था[3]। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (प्रबंधन और नियंत्रण लेना) अधिनियम, 1984 की संवैधानिक वैधता को असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में चुनौती दी गई थी: -

में महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाहौर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने की दृष्टि से पूरे भारत के लिए आम भाषा के रूप में हिंदी के प्रसार के लिए एक प्रस्ताव अपनाया और इस संकल्प के अनुसरण में गैर-हिंदी क्षेत्रों में हिंदी के प्रसार और प्रचार के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। शेष भारत में हिंदी के विकास और प्रसार के लिए सबसे पहले मद्रास शहर में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति के नाम से स्थापित किया गया, फिर वर्धा में। गांधी जी के समर्पित शिष्य स्वर्गीय बाबा राघब दास ने भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हिंदी के प्रसार का कार्य किया और 1934 में इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्थानीय नेता स्वर्गीय तरुण राम फूकन, स्वर्गीय नबीन चंद्र बरदालोई, स्वर्गीय गोपीनाथ बरदालोई, स्वर्गीय कृष्ण नाथ शर्मा और अन्य लोग बाबा राघब दास से जुड़ गए और 3 नवंबर को असम हिंदी प्रचार समिति नामक पहली संस्था का गठन किया गया। 1938 में गुवाहाटी में स्वर्गीय गोपीनाथ बरदालोई 1935 के अधिनियम के तहत असम के पहले मुख्यमंत्री थे। 1948 में असम हिंदी प्रचार समिति का नाम बदलकर असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कर दिया गया, जिसका मुख्य कार्यालय गुवाहाटी में था। समिति सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। सोसायटी में भारत के उत्तर-पूर्वी भाग के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिखरे हुए 22,000 से अधिक

[3] ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 2126.

व्यक्तियों की सदस्यता है। समिति के नियंत्रण में जिला समितियां हैं। समिति के दो संबद्ध निकाय भी हैं, अर्थात् मणिपुर हिंदी प्रचार सभा, इंफाल और असम राष्ट्रभाषा सेवक संघ। इस समिति का एकमात्र संविधान है जिसे बिधान के नाम से जाना जाता है जो गौहाटी में सोसाइटी रजिस्ट्रार असम के साथ भी पंजीकृत है। यह समिति एक साहित्यिक संस्था है। असम के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 230 के खंड 1 के तहत कार्य करने का इरादा रखते हुए असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अध्यादेश नामक एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश को 1984 के अधिनियम संख्या XXIII द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा वस्तुत समिति, जो कि एक सार्वजनिक निकाय थी जिसका गठन इसके सदस्यों द्वारा किया गया था जिसमें बायबस्थपिला सभा और कार्यपालिका का चुनाव किया गया था, को सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और समिति के सभी कार्यों, संपत्तियों और मामलों को इस बोर्ड द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था और यह अध्यादेश और अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई थी और अंततः अधिनियम चुनौती का विषय था। शीर्ष अदालत ने इस प्रकार कहा:

"इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह केवल नए सदस्यों को पेश करने के लिए नहीं है, न केवल यह कि सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले बोर्ड पर पूरा नियंत्रण छोड़ दिया गया है, व्यक्तियों के बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, इस तरह नामित व्यक्ति कोई भी हो सकता है और कोई नियंत्रण नहीं है। सोसाइटी का गठन करने वालों के लिए रखा गया है, जिनके पास एसोसिएशन बनाने का अधिकार था, उन्हें दूर रखा जाएगा और सोसाइटी को धारा 3 के अनुसार सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाया जाएगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि सम्मेलन अधिनियमों में जो किया गया था, जो ऊपर उल्लिखित संवैधानिक पीठ के फैसले में जांच के अधीन थे, इस मामले में बहुत कुछ किया गया है। इस मामले में वस्तुतः संघ के अधिकार को छीन लिया गया है और न केवल यह हर समय के लिए एक प्रकार का अभाव है क्योंकि यह भी प्रावधान नहीं है कि यह बोर्ड एक अंतरिम बोर्ड हो सकता है और उसके बाद एक उचित बोर्ड चुना जाएगा लेकिन यहां यह बोर्ड सोसाइटी के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करना जारी रखेगा। संविधान पीठ के मामले में उनके लॉर्डशिप

ने अनुच्छेद 19 (1) (सी) के दायरे पर उस अधिनियम में विचार किए गए संदर्भ में विचार किया और कहा:

> "हमारी राय में, एक संघ से अधिकार का अर्थ है कि एसोसिएशन बनाने वाले व्यक्तियों को केवल उन लोगों के साथ जुड़े रहने का अधिकार है जिन्हें वे स्वेच्छा से एसोसिएशन में स्वीकार करते हैं। कोई भी कानून, जिसके द्वारा सदस्यों को स्वैच्छिक एसोसिएशन में पेश किया जाता है, सदस्यों को उन्हें बाहर रखने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता है, या कोई भी कानून जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होने वालों की सदस्यता छीन लेता है, एक कानून का उल्लंघन होगा जो एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। यदि हम इस निवेदन को स्वीकार करते हैं कि अनुच्छेद 19 (1) (सी) द्वारा गारंटीकृत अधिकार एक संघ बनाने के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित है और एसोसिएशन को संस्थापकों द्वारा चुनी गई सदस्यता के साथ जारी रखने के अधिकार की रक्षा नहीं करता है या एसोसिएशन द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित है, तो यह अधिकार अर्थहीन होगा क्योंकि, जैसे ही एक संघ का गठन किया जाता है, इसकी संरचना में हस्तक्षेप करते हुए एक कानून पारित किया जा सकता है, ताकि गठित एसोसिएशन बिल्कुल भी कार्य करने में सक्षम न हो। यह अधिकार केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब एसोसिएशन को अपनी संरचना के साथ जारी रखने के अधिकार को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाता है, जैसा कि एसोसिएशन बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की गई है।"

> "इसलिए यह स्पष्ट है कि संविधान पीठ के आदेश के आधार पर भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का प्रबंधन अपने हाथ में लेने वाले अधिनियम और इस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना को संविधान के अनुरूप स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) का उल्लंघन करने वाला घोषित किया। उपरोक्त मामले में निर्धारित उक्ति का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, मैं मानता हूं कि अध्यादेश के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) का उल्लंघन करते हैं और इसलिए असंवैधानिक हैं।

14. इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। हमारे संविधान के तहत, किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित है। अनुच्छेद 300 ए निम्नानुसार है: -

"किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

15. किसी नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए, यह आवश्यक है कि एक वैध कानून होना चाहिए जो प्राधिकरण को कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान कर सके। जिस कानून के तहत प्राधिकरण कार्य करता है वह एक वैध कानून होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जिस कानून के तहत एक नागरिक संपत्ति से वंचित है, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 की परीक्षा पास करनी होगी। कानून मनमाना, अनुचित और मनमौजी नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि सरकार की विधायी कार्रवाई मनमानी, अनुचित और मनमौजी है, तो इसका परिणाम संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा निहित समानता से इनकार करना होगा (देखें मेनका गांधी का मामला[4])।

16. हमारी कानून प्रणाली में, यदि कोई नागरिक अपनी संपत्ति से वंचित है, तो उसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाना है। किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए विस्तृत प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 में निर्धारित की गई है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि मुआवजे का भुगतान अधिनियम की धारा 23 और 24 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना सोसायटी के सदस्यों को संपत्ति से वंचित करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। जहां तक अध्यादेश के प्रावधानों का संबंध समाज की परिसंपत्तियों को बिना मुआवजे के अध्यादेश के तहत गठित निगमित निकाय को हस्तांतरित करने से है, वे मनमाने, अनुचित और मनमौजी हैं। यह प्रावधान भी भेदभावपूर्ण है। यह भेदभाव किसी तर्कसंगत आधार पर आधारित नहीं है। जब अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपनी संपत्ति से वंचित प्रत्येक व्यक्ति को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 और 24 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मुआवजे

[4] ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 597.

का भुगतान किया जाता है, तो कोई कारण नहीं बताया जाता है कि वर्तमान मामले में सोसाइटी को किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना अपनी संपत्ति से वंचित क्यों किया गया है। अधिनियम के प्रावधान केवल इस विशेष समाज के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव करते हैं जिसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद कहा जाता है। इसलिए, मेरी राय में, अध्यादेश के प्रावधान स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

17. याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी तर्क दिया है कि अध्यादेश के प्रावधान संसद की विधायी शक्तियों से परे हैं। इस तर्क के लिए श्रीमती दमयंती नरंगा के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया जाता है। मैं उपर्युक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं और इसलिए, यह मानता हूं कि अधिनियम के प्रावधान विधायी क्षमता से भी परे हैं।

18. उपर्युक्त कारणों से अध्यादेश के प्रावधानों को संसद की विधायी क्षमता से परे और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ए) और 19 (1) (सी) का उल्लंघन करने वाला संविधान के दायरे से बाहर घोषित किया गया है। तदनुसार, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अध्यादेश को निष्पादित नहीं करने का निर्देश देते हुए परमादेश की रिट जारी की जाती है। यदि सोसायटी की सभी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो उन्हें सोसायटी को तुरंत लौटा दिया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा